

क्रान्ति सामय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 48 , 11 नवम्बर, शनिवार 2017, सूत, हिन्दी दैनिक

मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूत-गुजरात

सार समाचार

युवक ने की नर्स से छेड़छाड़

नोएडा। सेक्टर-168 स्थित छपरोली गांव के पास नर्स को झाड़ियों में खींचकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग आरोपी की ओर दौड़े लेकिन वह फ़ार हो गया। पीड़िता ने कोतवाली एक्सप्रेस वे में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।सेक्टर-168 छपरोली गांव में एक महिला परिवार के साथ रहती है। वह सेक्टर-33 स्थित एक अस्पताल में नर्स है। बुधस्पतिवार सुबह 8 बजे वह घर से अस्पताल के लिए निकली। रास्ते में गांव के ही जितेन्द्र उर्फ जीतू ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि जब उसने जीतू का विरोध किया तो वह उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में खींचने लगा। महिला के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे लोग आरोपी की ओर दौड़े तो वह भाग निकला। महिला का आरोप है कि आरोपी अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ी करता है। उसके कई बार समझाने पर भी आरोपी नहीं माना। एक्सप्रेस वे एसएचओ वेदपाल सिंह पुंडीर ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी को तलाश रही है।

गोली मारकर बिल्डर की हत्या दो सशस्त्र बदमाशों ने दिया घटना

साहिबाबाद। थाना साहिबाबाद क्षेत्र शालीमार गार्डन में बाइक सवार दो सशस्त्र बदमाशों ने एकता बिल्डर एंड इंजीनियर्स के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे 15 दिन पहले भी इसी बिल्डर की साइट पर दो बार बदमाश गोली चला चुके हैं। इसमें एक सुरक्षा गार्ड बदमाशों की गोली से घायल हो चुका है। उधर पुलिस को मौके से 12 कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार शाम करीब पांच बजे बाइक पर आये दो बदमाश बिल्डर एस्पपी सिंह के शालीमार गार्डन स्थित कार्यालय पर पहुंचे और बिल्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस पर बिल्डर ने भी अपनी लाइसेंस पिस्टल से बदमाशों पर फायरिंग की लेकिन बदमाश बच गए। उधर बिल्डर को कई गोलियां लगी थी। इस बीच एक बदमाश ने बिल्डर की कार को भी निशाना बनाकर कई गोलियां दागकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। बिल्डर को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां हालत खराब होने पर उसे यशोदा अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में वहां बिल्डर की मौत हो गई। मौत के खबर की सूचना पाकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप था 15 दिन पहले भी बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया था। मगर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। गोलीबारी की इस घटना से सभी बिल्डरों में रोष व्याप्त है। घटना की सूचना के एक घंटे बाद एसपी सिटी आकाश तोमर व एसपी अनूप सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की तहकीकात करने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। पुलिस को मौके से 12 कारतूस के खोखे बरामद किए। एसपी सिटी आकाश तोमर ने बताया कि बिल्डर की हत्या में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी गाजियाबाद हरिनारायन सिंह ने पुलिस चौकी शालीमार गार्डन इंचार्ज पर्वत चौहान को निलंबित कर दिया है। थाना साहिबाबाद के पूर्व इंचार्ज सुधीर त्यागी के खिलाफ जांच बिदा दी है। 10 दिन पहले हुए एक कातिलाना हमले में पहले ही हत्या का केस दर्ज है उसकी जांच की जा रही है। इस हत्या का कारण उन्होंने एक भूमि के टुकड़े पर विवाद बताया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर धरपकड़ के लिए भेजी गई हैं।

युवक से लूटा मोबाइल, तीन दिन बाद मामला दर्ज

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-20 क्षेत्र में एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने ई रिक्शा से जा रहे युवक से मोबाइल लूट लिया। तीन दिन से मामला दर्ज करने को लेकर युवक थाने के चक्कर काट रहा था। आखिर वीरवार को बमुश्किल मामला दर्ज हुआ। लाजपत नगर, नई दिल्ली निवासी कलिय एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। बीते छह नवंबर को वह बांटेनिकल गार्डन से ई रिक्शा में सवार होकर सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन के लिए आ रहा था, तभी सेक्टर-18 स्थित अट्टा पीर के पास एक बाइक पर सवार तीन बदमाश उनका मोबाइल लूटकर फ़ार हो गए। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की तथा पीड़ित को मामला दर्ज करने के लिए थाने भेज दिया। पीड़ित मामला दर्ज कराने के लिए थाने के तीन दिन से चक्कर काट रहा था।

गुवाहाटी। जीएसटी काउंसिल की आज होने जा रही बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स कटौती की घोषणा हो सकती है। 28 फ़ीसदी टैक्स स्लैब में शामिल रोजमर्रा की वस्तुओं, प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स और हाथ से बने फ़र्नीचर पर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। इससे रेस्तरां में खाना खाना सस्ता हो जाएगा। परिषद 28 प्रतिशत की उच्चतम कर स्लैब से करीब 80 फ़ीसदी वस्तुओं को बाहर करने पर और जीएसटी रिटर्न एक की जगह तीन माह में भरने जैसे निर्णयों पर भी मुहर लगा सकती है।

तीन माह के नतीजों पर भी होगा गौर सुर्जों के मुताबिक, परिषद जीएसटी लागू के तीन माह के परिणामों पर भी गौर करेगी। खासकर लघु उद्योगों पर इसके प्रभावों, एमआरपी को लेकर शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक में एकमुश्त कर योजना में एक समान कर, तमाम वस्तुओं पर कर घटाने, रिटर्न में आसानी से जुड़ी तीन समितियों की सिफरिशों पर फैसला लेना है। जीएसटी के दायरे में अभी 1200 के करीब वस्तुएं और सेवाएं हैं।

एक समान कर की मांग उल्लेखनीय है कि असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में एक

समिति बनाई गई थी, जिसे एकमुश्त कर योजना, एसी-गैर एसी रेस्तरां और तमाम वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा करनी थी। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष गरीश ओबेराय की अध्यक्षता में एक दल गुरुवार को राजस्व सचिव हसमुख अधिया से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सभी रेस्तरां पर एकसमान 12 फ़ीसदी कर की मांग की है। अगर इन सिफरिशों को स्वीकार कर लिया गया तो एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी राहत होगी।

छोटे कारोबारियों पर एक फ़ीसदी कर हो

समिति ने एकमुश्त योजना के तहत, व्यापारियों, मैयूफ़ेक्चरिंग (विनिर्माण) और रेस्तरां पर टैक्स एक फ़ीसदी करने की सिफरिश की है, अभी यह क्रमशः एक, दो और पांच फ़ीसदी है। एक करोड़ टर्नओवर वाले एकमुश्त योजना का लाभ उठा सकते हैं।

एसी-गैर एसी रेस्तरां पर 12 फ़ीसदी कर लगे

समिति ने एकमुश्त कर योजना से बाहर के एसी और गैर एसी रेस्तरां में कर का अंतर खत्म करने को भी कहा है। दोनों पर



ही एकसमान 12 फ़ीसदी कर का सुझाव दिया गया है।

अभी गैर एसी रेस्तरां पर 18 फ़ीसदी टैक्स है।

लगजरी होटलों पर भी कर बोझ कम होगा

समिति का कहना है कि 7500 से ज्यादा किराये के कमरे वाले होटलों में खाने-पीने पर 18 फ़ीसदी टैक्स लगाना चाहिए। इसमें पांच सितारा और अन्य होटलों में भेद नहीं हो। पांच सितारा होटलों पर अभी 28 फ़ीसदी टैक्स है।

28 फ़ीसदी टैक्स स्लैब से दो तिहाई

धुंध में कार यमुना में गिरी, दो छात्रों की मौत

कार में सवार थे पांच दोस्त

नई दिल्ली। तिमारपुर इलाके में बुधवार रात की धुंध की वजह से एक तेज रफ़्तार कार यमुना नदी में गिर गई। इस दर्दनाक घटना में कार में बैठे दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई जबकि तीन अन्य युवक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे। मृतकों की शिनाख्त दीपक जांगीड़ तथा कृष्णा यादव के तौर पर की गई। फ़िल्हाल पुलिस ने इस बाबत लापरवाही से मौत की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस सुर्जों के अनुसार दीपक जांगीड़ और कृष्णा यादव अपने परिवार के साथ हौजखास पुलिस कालोनी में रहते थे। उनके एक परिजन ने बताया कि दोनों

सभी ने पी रखी थी शराब, समझ नहीं आया रास्तावजीराबाद श्याम घाट के पास की घटना तीन ने किसी तरह बचाई जान

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। इनके बचपन के दोस्त आकाश व दीपक तिमारपुर के वजीराबाद गली संख्या 15 में रहते हैं।

बुधवार शाम को अचानक दीपक जांगीड़ और कृष्णा यादव का आकाश के फ़्लैट पर आने का कार्यक्रम बना। इसके बाद दीपक जांगीड़ अपनी कार से कृष्णा यादव के साथ वजीराबाद आकाश व दीपक के घर पहुंचा। इसके बाद चारों ने अपने एक और दोस्त आनंद को भी मौके पर बुला लिया, जो किंग्सवे कैम्प में रहता है। पुलिस ने बताया कि देर रात सभी पांच युवक कार से वजीराबाद के पास श्याम घाट पर पहुंचे थे। जहां देर रात तक घाट के समीप शराब पीने के बाद करीब डेढ़ बजे दीपक ने कार स्टार्ट

की और वहां से निकला लेकिन धुंध और नशे के कारण चालक रास्ता नहीं समझ पाया जिसके चलते उनकी कार यमुना नदी की तरफ चली गई। पुलिस ने दावा किया कि पानी में कार के जाने के बाद कार बाईं तरफ से पलट गई जिसकी वजह से चालक की सीट पर बैठा दीपक और पीछे बैठे आकाश और आनंद तो दरवाजा खोलकर बच निकले। लेकिन बाकी दीपक जांगीड़ और कृष्णा कार के साथ पानी में समा गए।

काफ़ी देर तक इन लोगों ने खुद से पानी में डूबे दोस्तों की तलाश की लेकिन पता नहीं चलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि देर रात ही दोनों के शवों को बाहर निकाला गया और इसकी सूचना उनके

परिजनों को दी गई। पूछताछ में पता चला है कि दोनों मृतक एनसीसी के कैडेट थे और वर्तमान में दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे थे।

इनमें दीपक के पिता प्रकाश सिंह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे लेकिन आंखों की रोशनी चले जाने के कारण उनकी जगह पर मां कविता सिंह को नौकरी मिल गई जो वर्तमान में आरकेपुरम थाने में तैनात हैं। वहीं कृष्णा यादव के हेड कांस्टेबल पिता की तबियत खराब होने के कारण उसकी मां कृष्णा देवी नौकरी कर रही हैं और वह वर्तमान में डीसीपी हौजखास के आफिस में तैनात हैं। घटना के बाबत बाकी बचे तीनों दोस्तों से पूछताछ की जा रही है।

सड़क के रास्ते दिल्ली पहुंचे यात्री

पायलट ने ड्यूटी आवर पूरे होने पर उड़ान से किया इनकार,

जयपुर। एयर इंडिया के एक पायलट ने कल रात ऐनवक पर विमान उड़ाने से इनकार कर दिया। विमान के कुछ यात्रियों को सड़क मार्ग से और कुछ यात्रियों को आज दूसरे एयरलाइंस के विमान से दिल्ली भेजा गया। सांगानेर हवाई अड्डे के निर्देशक जी एस बल्हारा के अनुसार दिल्ली से जयपुर आने वाली एयर इंडिया का विमान किन्हीं कारणों से देर रात डेढ़ बजे जयपुर पहुंचा था।

कुछ यात्री रुके होटल में

उन्होंने बताया कि यही विमान उड़ान संख्या 9आई 644 तकरीबन चालीस यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन विमान के पायलट ने अपने ड्यूटी समय समाप्त होने की वजह से विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया।

निर्देशक के अनुसार विमान के कुछ यात्रियों को रात में होटल में रूकवाया



गया, कुछ को सड़क मार्ग से भेजा गया। उन्होंने कहा कि रात में रूके यात्रियों को आज दूसरे एयरलाइंस के विमान से दिल्ली भेजा गया है। इधर, एयर इंडिया के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन सम्पर्क नहीं हुआ। जेएस बल्हारा ने बताया कि पायलट की ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था और वह दूसरी फ्लाइट नहीं ले सका। उन्होंने बताया कि डीजीसीए के नियमों के मुताबिक पायलट तय सुरक्षा कारणों से घंटों से ज्यादा समय तक अपना काम नहीं कर सकते हैं।

केंद्र सरकार समेत तीन राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के जानलेवा स्तर के महेनजर केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने इसे संविधान में निहित जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए तथा खतरे से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाने को लेकर प्राधिकारियों की निंदा की। आयोग ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और तीनों राज्यों की सरकारों से हालात से निपटने के लिए उठाए जा रहे एवं प्रस्तावित कदमों की दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एक बयान में कहा कि सरकार जहरीली धुंध के कारण नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं रोजमार्ग के केंद्रीय

मंत्रालयों के सचिवों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि उसने दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को गंभीरता से लिया है। आयोग ने कहा कि यह स्पष्ट है कि संबंधित प्राधिकारियों ने इस समस्या से निपटने के लिए वर्षभर उचित कदम नहीं उठाए, जो क्षेत्र के निवासियों के जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन के समान है। आयोग ने कहा कि वह स्वास्थ्य सचिवों से उम्मीद करता है कि वे प्रदूषण से प्रभावित लोगों का उपचार करने के लिए सरकारी अस्पतालों एवं अन्य एजेंसियों की तैयारी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दे। उसने कहा कि केंद्र और राज्यों में

एनएचआरसी ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा रहे व प्रस्तावित कदमों की जानकारी मांगी

एजेंसियों द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही पर्यावरणीय कानूनों के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा उचित अध्ययन किए जाने और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कदमों समेत उनकी सिफरिशों के उचित क्रियान्वयन को आवश्यकता है। लोगों की एहतियातन मेडिकल जांच कराए जाने की भी जरूरत है। एचएचआरसी ने कहा कि लगभग हर समाचार पत्र और टीवी चैनल इस विषय पर खबरें प्रसारित कर रहे हैं। शहर में

जहरीली धुंध खासकर जब सर्दी का मौसम आने वाला होता है, तब आने वाली एक वार्षिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। इसमें दिल्ली-एनसीआर में और इसके आसपास चल रहे निर्माण कार्य के साथ उड़ने वाले धूल के कण, वाहन, खासकर डीजल से चलने वाले ट्रक और भारी वाहन, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण हुए प्रदूषण, मानवीय नियंत्रण के बाहर शांत हवा की स्थिति और अत्यधिक नमी समेत कई कारणों का जिक्र किया गया है। आयोग ने कहा कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए और राजमार्गों को जोड़ने के लिए वैकल्पिक सड़कों के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। प्रदूषण बुधवार को खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और क्षेत्र में धुंध छाई

रही, जिसके कारण सरकार को रविवार तक स्कूलों को बंद करने, निर्माण गतिविधियों रोकने और शहर में ट्रकों के प्रवेश को रोक लगाने की घोषणा करनी पड़ी। एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) चेताने वाले स्तर पर पहुंच गया है। कुछ यंत्रों ने कुछ स्थानों पर 999 का अधिकतम एक्यूआई दर्ज किया। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में वायु गुणवत्ता इस कदर खराब हो गई है कि यह एक दिन में कम से कम 50 सिगरेट पीने के समान है। एक समाचार वेबसाइट ने रिपोर्ट दी कि हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक पर इसने एक हजार का आंकड़ा छू लिया है।

पांच मिनट में मार्कर बता देगा आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं

कानपुर। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए अब लंबी-चौड़ी जांच की जरूरत नहीं होगी। एक मार्कर महज पांच मिनट में बता देगा कि यह बीमारी है या नहीं। जीएसटीआर मेडिकल कॉलेज के अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल और आईआईटी-कानपुर के फिजिक्स विभाग के विशेषज्ञों ने इसके लिए एक उपकरण तैयार किया है, जिसे फिलहाल मार्कर (फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी डिवाइस) नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि जांच की इस तकनीक से बायोप्सी पर निर्भरता कम होगी। आगे चलकर यह बा इस उपकरण से यह भी पता चलेगा कि कैंसर है तो किस स्टेज में पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि इस उपकरण से जांच के दौरान मरीज को किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना होगा।



चांसलर या फिर दूसरी अर्थांरिटी ने छात्रों के व्यवहार को अनुशासन तोड़ने वाला करार दिया है। छात्रों को जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है, 'आपको एडमिन ब्लॉक के पास स्थित सीढ़ियों के पास बिरयानी पकाने और खाने का दोषी

पाया जाता है।' एबीवीपी की ओर से जारी प्रचार के बाद यह जुर्माना छात्रों पर लगाया गया है और इस वजह से यह मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एबीवीपी का आरोप है कि इस मौके पर यूनिवर्सिटी में बीफ पकाया गया था।

2 शनिवार 11 नवम्बर, 2017

गुणों से ही मनुष्य महान होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। महल के कितने भी ऊंचे शिखर पर बैठने से भी कौआ गरुड़ नहीं हो जाता -चाणक्य

सरकार या केंद्र

राजनीति में बड़ी महत्वाकांक्षा रखने वाले अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, यह विवाद ज्यादा गहराता गया है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली के शासन-सूत्र की वास्तविक शक्तियों का स्वामी कौन है ? दिल्ली की निर्वाचित सरकार या केंद्र का मनोनीत राज्यपाल ? कानून और संविधान के महत्त्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े इस विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ कर रही है। इस दौरान शीर्ष अदालत की टिप्पणियों से इसके संकेत मिल रहे हैं कि निर्वाचित सरकार के प्रति वह संवेदनशील है और उसके कामकाज के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने की पक्षधर है। हालांकि इसका यह भी मतलब निकाला नहीं जाना चाहिए कि शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार को वे सारी शक्तियाँ देने की इच्छुक हैं, जो दूसरे पूर्ण राज्यों को प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार? कानून और संविधान के सुब्रह्मण्यम के उस तर्क से सहमत नहीं है कि कैबिनेट की सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी होती है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशहै। लिहाजा, दिल्ली सरकार के कामकाज पर उपराज्यपाल की मोहर अनिवार्य है। बावजूद इसके शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में उपराज्यपाल की दखलअंदाजी को अनुचित माना है।

इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि दिल्ली सरकार संविधान के दायरे में रह कर कोई काम करती है तो उपराज्यपाल को उस पर दखल देने का कोई हक नहीं है। दरअसल, कानून, भूमि और पुलिस के मसले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ज्यादा टकराव रहा है और ये तीनों विषय गृह मंत्रालय के अधीन हैं। यह कहा जा सकता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का मूल कारण दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन अस्पष्ट न होना उतना नहीं है, जितना कि राजनीतिक अहं का होना है। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही है। उस दौरान वास्तविक अर्थों में दिल्ली का विकास हुआ। तब उन्हें भी वे शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त थे, जो आज केजरीवाल के पास है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि दिल्ली और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी।

अलबत्ता शीला दीक्षित को केंद्र का सहयोग प्राप्त था। लेकिन यह भी नहीं माना जा सकता कि केजरीवाल सरकार को वह सहयोग प्राप्त नहीं है। सहयोग परस्पर होता है। यदि केजरीवाल टकराव को मुख्य सियासी हथियार नहीं बनाये होते तो यह विवाद कोर्ट तक नहीं पहुँचता।

प्रदूषित पर्यावरण

प्रदूषण से आज हर कोई लस्त-पस्त है। प्रदूषित पर्यावरण की कड़ी मार आज बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक पड़ रही है। बड़ी दारुण स्थिति है। खासकर दिल्ली-पनसीआर का इलाका अपने विकास के उस बियावान में फंस कर उलझ गया है, जहां से निकलने में उसे बरसों लगेंगे और वह भी कठोर जिजीविषा दिखाने के बाद। मगर जिस तरह से राजधानी दिल्ली और उसके पास के इलाके दमघोँट या कहें गैस चेंबर में बदलते जा रहे हैं, वह चिंता तो पैदा करता ही है, यह सोचने को मजबूर करता है कि मोत की भुड़ी से छुटका पाये का उपाय क्या है ? जो उपाय पिछले दिनों बताए गए हैं, उससे सरकार की प्रदूषण से बच निकलने की जल्दबाजी ज्यादा दिखती है। ऐसे ‘‘मैडिकल इमरजेंसी’ के हालात में तात्कालिक उपाय तो जरूरी है ही; दीर्घकालीन रणनीति बनाने की महती आवश्यकता है।

ठीक है कि एनसीआर के स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश है या मेट्रो के फेरे बढ़ाने की बात है या ट्रकों को रात में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने का नियम लागू कर दिया गया हो या पार्किंग की दर चार गुना बढ़ा दी गई हो। लेकिन क्या ऐसे उपायों से हम एक बड़ी आबादी को राहत दे पाने की स्थिति में हैं ? पार्किंग का किराया चार गुना बढ़ाने का तर्क सौ फीसद अताकिर्क है। एक तरफ हम मेट्रो के फेरे बढ़ाते हैं वहीं दूसरी तरफ पार्किंग की दर में बेतहाशा वृद्धि करते हैं। हमें व्यावहारिक नियम-कायदों और समाधान के रास्ते तलाशने होंगे।

पर्यावरण की शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू करनी होगी। हम विकास की सीढ़ियां भले द्रुत गति से नाप रहे हों किंतु जब तक शुद्ध हवा, जल और खान-पान की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक हर विकास बेमानी है। ऐसे विकास से क्या लाभ जो आराम और निश्चिंतता का बोध कराने के बजाय डराएं और चिढ़ाएं। जो हालात दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर की अवाम श्लेह रही है, उस पर संजीदा होना ही पड़ेगा वरना हमारे दिन गिनती के ही रह जाएंगे। यहीं नागरिक जिम्मेदारी की हद शुरू होती है।

सत्संग

मनुष्य के संकीर्ण मन

आपका लक्ष्य सफलता पाना था और आपने कड़ी मेहनत की, मगर नतीजा विपरीत हो गया। इसे लेकर किसलिए परेशान होना ? तकलीफकिसलिए ? कभी उत्साह के साथ बड़ रही चींटियों की कतार को देखिए। उनमें से एक चींटी की राह पर यों ही उंगली रखकर रास्ता रोककर देखिए। वह रु केगी नहीं। उंगली के चारों ओर घूमते हुए ढुंढेगी कि रास्ता कहाँ है ? उसके रास्ते पर चाहे जितने रोड़े अटकाएँ वह किसी न किसी तरह अपनी यात्रा जारी रखेगी। मर कर गिर जाने तक वह अपना उत्साह नहीं खोती। पतली-सी घास को जमीन से उखाड़कर उसकी जड़ों को गौर से देखिए। कितने उत्साह के साथ जमीन के अंदर गहराई में जड़ों को फैलाकर वह धरती में टिकी होती है। आपकी छत के ऊपर जरा-सी मिट्टी और थोड़ी नमी मिल जाए तो कोई घास खुद को वहां खड़ा करने की कोशिश करेगी। दो पत्ते पैदा करके सूर्य की ऊर्जा पाने की कोशिश करेगी। यह प्राणशक्ति ऊबना नहीं जानती। मनुष्य के संकीर्ण मन में ही गुस्सा, झुंझलाहट और नाउम्मीदी पैदा होती है। खुद को ‘‘पस्त’’ होने की इजाजत देने वाला प्राणी इंसान ही है। आपकी इच्छा के मुताबिक किसी ने व्यवहार नहीं किया। आपकी उम्मीद के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। सरल शब्दों में कहें तो आपको जो हासिल हुआ है, उसे स्वीकार करने में असमर्थ होकर आप मन ही मन नपस्त करते हैं, विरोध करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा, ‘‘हार को न श्लेे पाने की वजह से मन में निराशा और खौझ आने पर ही तो कामयाबी पाने की तड़प और आक्रोश पैदा होते हैं ?’’ हार से गुस्सा आएगा, निराशा आएगी और ये आपको उठाकर विजय के द्वार पर पहुंचा देगी, यह हास्यास्पद विचार है। तड़प के बल से भले ही आप जीत हासिल कर लें, लेकिन वह नाममात्र की जीत होगी। उससे आपकी कोई भलाई नहीं होगी। पस्त होने के बाद आप चाहते हैं कि अगला आदमी आपके मन को समझे, दूसरे लोग आपके साथ बैठकर रोएं। कैसा पागलपन है ये ? ऐसी उम्मीद करना कहाँ का न्याय है कि दुनिया आपका मन रखने के लिए अपने साथ ठगी करे ? निराशा आत्मविास को ध्वस्त कर देती है। हथियार लेकर बाहर से हमला करने वालों से तत्काल आफत आ सकती है। उसी समय सही रणनीति बनाकर उनसे निपटना भी आसान है। लेकिन मन की निराशा जो है, अंदर बैठी हुई वह आपको चीर-कुतरकर बरबाद करने वाले विषैले हथियार के समान है।

संपादकीय

‘‘टेस्ट केसेस’’

हकीकत यह है कि ये कंपनियां कार्य करती ही नहीं थीं और एक खोल के रूप में अस्तित्व में थीं, जिन्हें ‘‘शेल कंपनी’’ कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अपना लेखा जोखा रजिस्ट्रार ऑफकंपनीज को पिछले तीन साल से नहीं दे पायीं थीं। इस कमी को आधार बना कर इनको रिकॉर्ड में से समाप्त किया गया। इसके अलावा, लगभग उनके तीन लाख नौ हजार डायरेक्टर भी अयोग्य किए गए हैं। यह संभव हुआ उन आंकड़ों का संज्ञान लेकर जो कि सरकार को नोटबंदी के उपरांत बैंकों से प्राप्त हुए। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 58000 खातों द्वारा 17000 करोड़ की रकम को अवैध रूप से जमा किया गया एवं निकाला गया। देश में अच्छे स्वतंत्र डायरेक्टर उपलब्ध नहीं है और फर्जी डायरेक्टरों की भरमार है। यह सब कुछ ऐसा है कि मानो शेर को जंगल में शिकार नहीं मिला हो और वह गांव पर हमला कर दे या किसी शिकारी की नजरों से अगर देखा जाए तो यह प्रक्रिया शुरू में चारे को डाल कर शिकार पकड़ने वाली प्रक्रिया थी।

सतीश पेडणेकर

कोर्ट सिर्फ पोस्टमॉर्टम के लिए ही न हों। उसे न केवल फ्रॉड एवं भ्रष्टाचार के अपितु अच्छे खातों में भी ‘‘टेस्ट केसेस’’ के तौर पर झांकने का अवसर मिले। आखिरकार अब सीबीसी ने 2001 से आज तक हुए फ्रॉड्स की रिपोर्ट मांगी है। तीन करोड़ रुपये से ऊपर के इन फ्रॉडों की संख्या काफी ज्यादा होगी और इसके उद्देश्य क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसे एक पैटर्न की स्टडी के लिए डाटा मांगना कहा जा रहा है मगर इसके कई और आयाम हैं। धन के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में सरकार ने दो लाख चौबीस हजार कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड में से समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व अब नहीं रहा और वह अब अपने कार्य को नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि ये कंपनियां कार्य करती ही नहीं थीं और एक खोल के रूप में अस्तित्व में थीं, जिन्हें ‘‘शेल कंपनी’’ कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अपना लेखा जोखा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पिछले तीन साल से नहीं दे पायीं थीं। इस कमी को आधार बना कर इनको रिकॉर्ड में से समाप्त किया गया। इसके अलावा, लगभग उनके तीन लाख नौ हजार डायरेक्टर भी अयोग्य किए गए हैं। यह संभव हुआ उन आंकड़ों का संज्ञान लेकर जो कि सरकार को नोटबंदी के उपरांत बैंकों से प्राप्त हुए। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 58000 खातों द्वारा 17000 करोड़ की रकम को अवैध रूप से जमा किया गया एवं निकाला गया।

देश में अच्छे स्वतंत्र डायरेक्टर उपलब्ध नहीं है और फर्जी डायरेक्टरों की भरमार है। यह सब कुछ ऐसा है कि मानो शेर को जंगल में शिकार नहीं मिला हो और वह गांव पर हमला कर दे या किसी शिकारी की नजरों से अगर देखा जाए तो यह प्रक्रिया शुरू में चारे को डाल कर शिकार पकड़ने वाली प्रक्रिया थी, जो बाद में अब ढोल बजा के शिकार को मांद में से निकालने सरीखी हो। मगर रास्ता चाहें जो भी अपनाया जाए; असल बात तो टैक्स चोरी को रोकना एवं निष्क्रिय धन को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाने की है। इस प्रयास में सरकार तरह-तरह के उपाय कर रही है। अभी हाल ही में एक बड़ी आईटी कंपनी को काफी बड़ा ठेका (लगभग 600 करोड़ रुपये का) सोशल मीडिया इंटेलिजेंस द्वारा कर चोरी का पता लगाने के लिए दिया गया है। इतना सब प्रयास इसलिए करने पड़ रहे हैं कि ‘‘जुगाड़’’ हम भारतीयों की नस-नस में है। स्टार्टअप या एप भी इसी ‘‘जुगाड़’’ का प्रतिरूप हैं। अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन नोटबंदी के दौरान लोगों ने बैंक वालों की मदद से खूब किया। कस्टमर को भगवान मानने की हिदायत वाले पोस्टर बैंकों में लगे ही हुए थे और इस बात को समझने में कहीं-कहीं बैंक वालों की भी भूल हुई की वे रातों-रात इनकम टैक्स अधिकारी बन चुके थे। खेर ! जो हुआ सो हुआ, मगर अब जो आगे-आगे हो रहा है वह क्रांतिकारी ही कहा जाएगा। आज तक किसी ने कंपनियों से नहीं पूछा था, जब तक की वह कोई ऋण लेने किसी

चलते चलते

‘‘प्रभुवर्ग’’

दुनिया के सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफार्म में शुमार किया जाता है। यहां बड़ी तादाद में दुनिया की प्रभावशाली हस्तियों का जमावड़ा है। जिनकी लिखी 140 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी खबर बनती है और बहस का विषय भी। बिहारी ने कई बरस पहले लिखा था, ‘‘देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर’’। यानी छोटें में कही गई बात ज्यादा मारक होती है। नि:संदेह 140 शब्दों की सीमा ने ट्विटर को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक तबका 140 शब्दों की सीमा का आलोचक भी रहा। वह इसे ‘‘दमघोँटू’’ बताते रहे। शायद, आलोचना-समालोचना के दायरे से ट्विटर खुद निकल कर चहचहाना चाहता था। सो उसने शब्दों की सीमा को अब दोगुना कर दिया है। बिंदास 280 शब्द। मगर उपयोगकर्ताओं ने इस तब्दीदी की तीखी

मुद्दा

टी-20 सीरीज

भारतीय कप्तान विराट कोहली का सितारा आजकल बुलंदी पर है। इस कारण सफलताएं भी उनके नाम के साथ जुड़ती चली जा रहीं हैं। अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टी-20 सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। इंद्र देवता की मेहरबानी से पिछली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में एक-एक से बराबरी रह गई थी। इस सीरीज के तीसरे मैच में भी बारिश के कारण काफी समय तक लगता रहा कि मैच शायद ही हो पाए। पर आखिर में आठ-आठ ओवर के मैच में भारत ने छह रन से विजय पाकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। विराट कोहली और रवि शास्त्री का कप्तान और कोच का तालमेल बनने के बाद पर भारतीय टीम बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर है, वनडे में दक्षिण अफ्रीका के बराबर 120 रेटिंग अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। पर विराट और शास्त्री की जोड़ी टी-20 में पांचवीं रैंकिंग को सुधार दे तो भारत का विश्व क्रिकेट पर दबदबा बन सकता है। हां, इतना जरूर है कि न्यूजीलैंड टीम इंडिया की अच्छे से परीक्षा लेने में सफल रही। वह अनुकूल स्थितियों में खेलने पर हम पर भारी पड़ सकती है, इस बात का उसने अहसास

जरूर करा दिया है। भारतीय टीम तीनों फाग्रेट में संतुलित नजर आती है। इस टीम में कोहली का आगे बढ़कर नेतृत्व, रोहित शर्मा और शिखर धवन की दमदार ओपनिंग जोड़ी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की पेस जोड़ी के साथ हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड तड़का विजेता का स्वरूप प्रदान करता है। रोहित और शिखर की जोड़ी को हम दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ियों में शुमार कर सकते हैं। वहीं बुमराह और भुवनेश्वर ने डेथ ओवरर्स में बल्लेबाजों को बांधने की कला विकसित करके दुनियाभर के बल्लेबाजों पर कहर बरपाया हुआ है।

वहीं पांड्या के रूप में देश को ऐसा पहला पेस गेंदबाजी वाला ऑलराउंडर मिला है, जिसमें विशेषज्ञों को दूसरा कपिल देव दिखने लगा है। इस टीम की मजबूती को इससे समझा जा सकता है कि कुछ समय पहले तक सभी प्रारूपों में देश के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर माने जाने वाले रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पिछली तीन छोटे प्रारूप की सीरीज के लिए टीम में जगह तक नहीं पा सके हैं।

यजुर्वेद चाहल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव

स्पिन अटैक की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला हुआ

है। यही नहीं देश के सर्वश्रेष्ठ पेस गेंदबाज माने जाने वाले उमेश यादव और मोहम्मद शमी भी छोटे प्रारूप की टीम में स्थान नहीं बना सके हैं। मौजूदा समय में टीम प्रबंधन के पास इतने गेंदबाज हैं कि किसी के भी चोटिल होने पर उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं रह गई है। यह जरूर है कि स्पिन अटैक में

वित्तीय संस्था के पास न जाएं, कि आप के ‘‘मेमोरे’डम ऑफ एसोसिएशन’ एवं ‘‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ का पालन कर भी रही है कि नहीं कर रहीं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की हैसियत एक जनम-मरण पंजीकरण कार्यालय से अधिक कभी महसूस नहीं की गई थी। परन्तु इस तरह का बड़ा कदम उठा कर सरकार ने इस ओर बरती जाने वाली उदासीनता को एक झटके में समाप्त किया है। वहीं, हमारे देश की दिलचस्प बात यह है कि यहां कई कानूनों का उद्देश्य कुछ और होता है मगर उनका इस्तेमाल किसी और ही एरिया में होने लगता है। उदाहरण के लिए बीआईएफ्आर (बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एंड फाइनैसियल रिकंस्ट्रक्शन) का उपयोग कंपनियों ने बीमार व्यवसाय को ठीक करने के लिए हुआ था। किंतु कंपनियों ने बोर्ड के अधिकारियों के साथ तालमेल मिला कर अपने आपको अन्य कानूनों के अंतर्गत वसूली प्रक्रियाओं से बचाने के लिए इसका उपयोग किया। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और अब बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार ‘‘सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्कस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफसिक्योरिटी इंटरेस्ट्स (सरफेसी एक्ट) कानून’ एक नये प्रकार की फंडिंग प्रोडक्ट्स के उद्देश्य से किया गया था। मगर इस कानून का उपयोग रिकवरी के लिए ही हुआ। इधर भी कोई-न-कोई एंज मिलीभगत के चलते ऋा वसूली में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी वरना जब ये कानून आया था तो लगता था अब बैंकों के ऋा वसूल हो जाया करेगे मगर ऐसा नहीं हुआ। आज पूरी पश्चाली सक्रिय है। नये-नये कानून आ रहे हैं। हालांकि कुछ नये कानून अभी मीडिया का उतना ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे जितना कि ‘‘जीएसटी’’ ने किया। ऐसा ही एक कानून है ‘‘इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड’। दिलचस्प बात है कि इस कानून को ‘‘इज ऑफ डूइंग

जब ऋा देते समय बिजनेस की ताकत एवं प्रक्रिया में ईमानदारी एवं पारदर्शिता का कड़ाई से पालन हो। क्यों न इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था हो जो केस को कभी भी जांच के लिए मंगा सके। कोर्ट सिर्फ पोस्टमॉर्टम के लिए ही न हों। मतलब यह कि न केवल फ्रॉड एवं भ्रष्टाचार के अपितु अच्छे खातों में भी ‘‘टेस्ट केसेस’ के तौर पर झांकने का अवसर मिले। आखिरकार अब सीबीसी ने 2001 से आज तक हुए फ्रॉड्स की रिपोर्ट मांगी है। तीन करोड़ रुपये से ऊपर के इन फाईों की संख्या काफी ज्यादा होगी और इसके उद्देश्य क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऊपरी तौर पर कहा जा रहा है कि एक पैटर्न की स्टडी के लिए यह डाटा मांगा जा रहा है मगर इसके कई और आयाम हैं।

भ्रष्टाचार पर प्रहार

आभा स्वामी
भारत में बहुत-से लोगों को लग सकता है कि यह दूर की खबर है, लेकिन सऊदी अरब में 11 शहजादों, चार मंत्रियों और अनेक पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी ऐसी घटना है, जिससे अपने यहां भी सीख ली जा सकती है। ये कार्रवाई शाही आदेश से भ्रष्टाचार विरोधी समिति के गठन के कुछ ही घंटों के बाद हुई। ये समिति क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में बनी है। 32 वर्षीय क्राउन प्रिंस सलमान ने अपनी छवि एक सुधारक की बनाई है। सामाजिक जीवन में उनकी पहल पर कई उदारवादी फैसले लिए गए हैं। इतमें महिलाओं को ड्राइविंग की मिली छूट भी शामिल है। अब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इसकी शुरुआत उन्होंने बेहद रसूखदार लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए की। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अक्सर छवि निर्माण में लगे शासक निम्नस्तरीय अधिकारियों या छोटे-मोटे व्यवसायियों पर कार्रवाई करके प्रचार पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस सलमान ने शुरुआत अपने सऊदी राजपरिवार से जुड़े लोगों से की। राजपरिवार के गिरफ्तार हुए सदस्यों में अरबपति शहजादे अलबलौद बिन-तलाल भी हैं। सऊदी अरब लोकतांत्रिक देश नहीं है। माना जाता है कि लोकतंत्र में उच्च-पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही तय रहती है। वहां पारदर्शिता होती है, इसलिए भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। जबकि राजतंत्र या तानाशाही व्यवस्थाओं में शासक निरंकुश होते हैं, अतः वे मनमर्फी चलाते हैं। लेकिन सऊदी अरब की ताजा मिसाल और चीन के हालिया घटनाक्रम को सामने रखें, तो इस धारणा पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ सकती है।

पांच साल पहले देश की कमान संभालने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफअपना बहुचर्चित अभियान शुरू किया। उन्होंने बाय और मक्खियों (यानी उच्च या निम्न पदस्थ भ्रष्टाचारियों) दोनों को ही ना बर्खाने का इरादा जताया। आम राय है कि उनका अभियान काफी प्रभावी रहा है। दरअसल, चीन की सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत होने का यह भी एक बड़ा कारण है। ये बात शी के संदर्भ में कही गई और अब क्राउन प्रिंस सलमान के मामले में भी दोहराई जा रही है कि असल में ये नेता अपनी सत्ता मजबूत करने और अपने विरोधियों को निपटाने के मकसद से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चला रहे हैं। संभव है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। ऐसी खबरें आई थीं कि क्राउन प्रिंस की बढ़ती ताकत से सऊदी राजपरिवार में असंतोष है। इसके बावजूद इतनी बड़ी कार्रवाई को महज सत्ता-संघर्ष का परिणाम नहीं माना जा सकता।

कदम मजबूत इरादे वाले नेता ही उठा पाते हैं। भारत जैसे देशों के लिए इसमें एक सबक छिपा है। अपनी लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व करते हुए भी हमें अक्सर ये अप्सोस होता है कि अपने यहां भ्रष्ट नेताओं या कारोबारियों का असल में कुछ नहीं बिगड़ता। कई मामलों में सरकारों की अनिच्छा, तो कुछ मामलों में धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। इसकी भारी कीमत जनता चुकाती है। क्या यह संभव नहीं है कि लोकतंत्र को कायम रखते हुए भी हम चीन या सऊदी अरब जैसा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अपने देश में भी चला सकें?

खांडेला नागरिक परिषद का स्नेहमिलन कल

सूरत। खांडेला नागरिक परिषद की ओर से 12 नवंबर, रविवार को स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। मेहंदौपुर बालाजीधाम, न्यू सिटीलाईट रोड, सूरत में आयोजित होने वाले स्नेह मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्मयुजिकल हाउजी, मैजिक सहित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत रविवार की शाम 5.30 बजे से होगा।



सूरत। संजय लीला भंसाली के फिल्म रानी पद्मावती को लेकर अब विरोध और तेज हो गया है। शुक्रवार को विश्व हिन्दु परिषद के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने पत्रकार परिषद के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि हिन्दु धर्म पर प्रहार करने वाले किसी भी फिल्म को बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

लिम्बायत से मिला

नवजात शिशु

सूरत। लिम्बायत के गोडादरा स्थित रेलवे फाटक के निकट की सम्राट इंडस्ट्रीइयल के झोपड़े में पुलिस ने लावारिश अवस्था में पड़े एक जीवित दो माह के नवजात बच्चे का कब्जा लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया है। स्मीमेर अस्पताल के अनुसार गुरुवार की रात में लिम्बायत पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गोडादरा रेलवे फाटक स्थित सम्राट इंडस्ट्रीयल सोसायटी के एक झोपड़े में दो माह का एक अनजान मासूम नवजात बच्चा रो रहा है।



सूरत। शहर में यमदूत की तरह सड़को पर 24 घंटे घुम रहे ट्रकों ने शुक्रवार को एक और युवक को अपना शिकार बनाया। शहर के मंगहला रोड से बाइक से गुजर रहे युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। जिससे युवक की घटना स्थल पर ही दर्द नाक मौत हो गई।



सूरत। शहर के सग्राम पुरा क्षेत्र स्थित प्राचीन क्षेत्र पाल दादा मंदिर में काल भैरव अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत सहित विद्वत ब्राह्मणों ने यज्ञ में आहुति डाल कर विश्व कल्याण की कामना की।

वराछा पुलिस ने 3.50 लाख का गांजा बरामद की

सूरत। वराछा पुलिस को सूचना मिलने पर थाना क्षेत्र के अश्वनी कुमार रोड स्थित अशोक नगर झोपड़पट्टी के एक मकान में छापा मारकर 3 लाख 50 हजार का गांजा बरामद किया है बंद मकान में छिपाकर रखा 58.19 किलोग्राम गांजा पुलिस में जब्त किया। वराछा पुलिस के अनुसार स्टाफ के पुलिसकर्मियों को सूचना मिली थी कि वराछा के अश्वनी कुमार रोड स्थित रेलवे पटरी के निकट की अशोक नगर झोपड़पट्टी के मकान नंबर 45 में गांजे का खजोरा छिपा कर रखा है।

शिवसेना गुजरात की 50 से 75 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

अहमदाबाद (ईएमएस)। शिवसेना ने भी आज गुजरात विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव पर देश नहीं बल्कि दुनिया की नजरे टिकी हुई हैं। केन्द्र की एनडीए सरकार की सहयोगी शिवसेना ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। शिवसेना ने यह भी ऐलान किया कि वह गुजरात में किसी भी राजनीतिक दल से

गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि आखिरी फैसले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही करेंगे। शिवसेना की ओर से इसकी योजना बनाए जाने के बाद पार्टी का एक उच्चस्तरीय दल चुनी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और चुनावी एजेंडे का निर्णय करने में जुटा हुआ है। इस ऐलान के बाद फिर एक बार भाजपा और शिवसेना के संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ समय पहले चर्चा थी कि शिवसेना भी चुनावी जंग में कूद सकती है और आज उसने ऐलान कर दिया कि वह 50 से

75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 50 से 75 सीटों में ज्यादातर अहमदाबाद और सूरत की होंगी, जहां महाराष्ट्रीय मतदाता ज्यादा हैं। इसके अलावा राजकोट की भी कई सीटों पर शिवसेना उम्मीदवार खड़े कर सकती है। शिवसेना हिन्दुत्व के मुद्दे को लेकर गुजरात में चुनाव प्रचार करेगी। गौरतलब है कि शिवसेना, भाजपा की सहयोगी पार्टी है, लेकिन पिछले काफी समय से उसकी गतिविधियां भाजपा विरोधी के संकेत दे रही है। एनसीपी मुखिया

शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात काफी कुछ कहती है। इसके अलावा पास संयोजक हार्दिक पटेल के साथ फरवरी में हुई मुलाकात से साफ है कि गुजरात में शिवसेना, भाजपा विरोधी रणनीति के साथ आगामी चुनाव में उतरेगी। हालांकि शिवसेना के लिए गुजरात में अनेक चुनौतियां हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शिवसेना ने यह कदम गुजरात में भाजपा को कमजोर करने के लिए उठाया है।

एनआईडी के आसिस्टन्ट प्रोफेसर 17 दिनों से लापता

अहमदाबाद (ईएमएस)। चांदखेडा क्षेत्र के गोदरेज गार्डन सिटी निवासी और गांधीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) के आसिस्टन्ट प्रोफेसर पिछले 17 दिनों से लापता हैं। प्रोफेसर की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के चांदखेडा क्षेत्र के गोदरेज गार्डन सिटी में 25 वर्षीय नलीन मनी अपनी पत्नी मनीषा के साथ रहते थे। नलीन

मनी गांधीनगर की एनआईडी में बतौर आसिस्टन्ट प्रोफेसर सेवारत थे। गत 22 अक्टूबर की रात्रि भोजन करने के बाद पति-पत्नी सो गए थे। दूसरे दिन सुबह नौ बजे मनीषा जगी तो नलीन मनी नहीं देखा। मोबाइल पर नलीन मनी का कालेज जाने का मैसेज मिलने पर मनीषा ने मान लिया कि उनके पति कालेज गए होंगे। बाद में नलीन मनी के लेपटोप में दिल्ली के फ्लाइट की टिकट मिली। मनीषा ने नलीन मनी को

फोन किया तो उनका मोबाइल बंद था। जिसके बाद मनीषा ने दिल्ली स्थित नलीन मनी के मामा को फोन किया। उन्होंने कहा कि नलीन आज दिल्ली आनेवाला था, लेकिन अब तक आया नहीं है। बाद में मनीषा ने अहमदाबाद स्थित नलीन के दोस्तों और नाते-रिश्तेदारों से पूछताछ की। लेकिन नलीन के बारे में कोई अता पता नहीं मिला। नतीजतन मनीषा ने चांदखेडा पुलिस थाने में नलीन के लापता होने की सूचनायें रपट दर्ज करवा दी।

उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा और कांग्रेस की बैठक आज

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस और भाजपा की बैठकों का दौर कल से प्रारंभ होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को में कल नई दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा भी उम्मीदवारों को लेकर कल बैठक करेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निवास पर 10 से 12 नवंबर के दौरान भाजपा पार्लामेंटरी बोर्ड की बैठक होगी। जिसमें उम्मीदवारों

बिना आरक्षण भी काफी कुछ किया जा सकता है: सैम पित्रोदा

अहमदाबाद (ईएमएस)। एक तरफ कांग्रेस जहां गुजरात में पाटीदारों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल के साथ बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बिना आरक्षण दिए भी काफी कुछ किया जा सकता है। सैम पित्रोदा पांच के गुजरात दौर पर हैं। वह वहां कई वर्गों के लोगों से मुलाकात कर रहे

हैं। इस दौरान ही पित्रोदा ने कहा है कि विकसित होने के लिए हर किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। हां, कुछ ऐसे वर्ग हैं, जिन्हें कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जा सकती हैं। बता दें कि सैम पित्रोदा को गहुल गांधी के करीबियों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां गुजरात चुनाव काफी नजदीक हैं। जब कांग्रेस लगातार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के समर्थन के लिए उनसे बातचीत कर रही है, तब पार्टी थिंकटैंक

के एक बड़े नेता का यह बयान चौंकाता है। बता दें कि बुधवार शाम की कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और पाटीदार आरक्षण समिति की बैठक बेनतीजा रही थी। देर रात 3 घंटे तक चली मैगधन बैठक में संवैधानिक तौर पर कांग्रेस किस तरीके से आरक्षण देगी, इस विषय पर पाटीदार नेताओं ने सवाल उठाए। हालांकि बैठक के बाद पाटीदार नेताओं ने कहा कि उनकी मुलाकात बेहद अच्छे माहौल में हुई।